संपादकीय

मौलिक प्रतिभा के विकास में है बाधक

पिछले दिनों आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रो. सुमन च वर्ती के उस बयान ने चौंकाया कि कोचिंग के कारोबार ने छात्रों की सोचने की क्षमता को घटाया है। वे प्रतिभा विस्तार व मौलिक सोच में विकास के बजाय कोचिंग उद्योग के चतुराई के खेल में शामिल हो रहे हैं। वे दिमाग के इस्तेमाल के बजाय जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए ट्रिक्स से गलत ऑप्शन हटाना सीख रहे हैं। फलतः वे आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश तो पा जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा से साम्य बैठाने में असफल साबित होते हैं, जिससे उनकी आईआईटी में बैक लगने यानी कुछ विषयों अनुतीर्ण होने से बैक लगने की स्थिति पैदा हो रही है। जिससे वे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। हो सकता आने वाले समय में किसी अध्ययन व शोध से यह बात सामने आए कि उच्च तकनीक संस्थानों में बढ़ती आत्मघात की प्रवृत्ति के पीछे कोचिंग संस्थानों की भेड़चाल से उपजी विसंगतियां हों। निश्चय ही यह स्थिति भारतीय उच्च व तकनीकी संस्थानों में विकसित हो रही इस नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। एक समय था कि भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रणाली में स्वस्थ स्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिभावान विद्यार्थी ही उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा सकते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाजार के लगातार बढ़ते दखल ने सारी स्थिति ही उलट कर रख दी। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों द्वारा सौ फीसदी तक अंक दिए जाने ने राज्यों के बोर्डों से परीक्षा उतीर्ण करने वाले छात्रों को हीन भावना से भर दिया। निःसंदेहद, वह शिक्षा प्रणाली सवालों के दायरे में आनी चाहिए, जिसमें असंभव से लगने वाले सौ फीसदी अंक छात्रों को दिए जाते हैं। सौ फीसदी अंक एक नहीं कई-कई छात्रों को दिए जाते हैं। वहीं राज्यों के विभिन्न बोर्डों में परीक्षक कंजूसी से नंबर देकर पहले ही छात्रों को राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर कर देते हैं। निश्चय ही यह स्थिति देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय जैसी है। दरअसल, देश में पहले भी कोचिंग व्यवस्था मौजूद रही है। लेकिन एक सहायक की भूमिका में। आज कोचिंग कारोबारियों द्वारा उसे छात्रों के भविष्य का निर्धारण करने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में बताया जा रहा है। यह व्यवस्था देश में व्याप्त आर्थिक विभेद को भी और बढ़ाती है। तय है कि संपन्न घरों से आने वाले बच्चे महंगी कोचिंग पाकर गुदड़ी के लालों के जीवन पर सदैव भारी पड़ेंगे। फलतः कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के अभिभावक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कर्ज लेकर कोचिंग का जुगाड़ करते हैं। अपना पेट काटकर वे बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। कई अभिभावक अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। वहीं शैक्षिक गुणवत्ता के नजरिये से देखें तो पहले जब कोचिंग एक सहायक की भूमिका में थी तो छात्र विस्तृत पढ़ाई से विषय को समझने का प्रयास करते थे। अब पूरी व्यवस्था कोचिंग केंद्रित होने से शिक्षा की व्यापकता खत्म हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में सवाल समझकर हल करने की बजाय गलत विकल्पों को हटाने की कोचिंगस द्वारा सिखायी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, कोचिंग संस्थानों के तौर-तरीकों से छात्रों को 'स्पून फीडिंग' की लत लग जाती है।

विनोद शर्मा, संपादक

उद्योग जगत की खुशी बंगाल के फिर से निवेश और नौकरियों का केंद्र बनने का संकेत है

ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के बंद होने की घटना के बाद बंगाल में बड़े उद्योग लगाने को लेकर निवेशकों में एक तरह की हिचक पैदा हो गई। परिणाम यह हुआ कि रोजगार के अवसर घटे और लोगों का पलायन बढ़ने लगा। हालांकि अब जब भाजपा की सरकार बनी है, तो उद्योग जगत में एक बार फिर सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई उद्योग संगठनों का कहना है कि वह आने वाले समय में सरकार को नई परियोजनाओं की रूपरेखा सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से गति मिल सकती है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल एक नए अवसर के दौर में प्रवेश कर रहा है।

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम केवल राजनीतिक बदलाव ही नहीं लाये बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर नई उम्मीदें भी जगाई हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका की प्रतिक्रिया ने इस चर्चा को और गति दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल का व्यापारिक वर्ग इस परिणाम से खुश है और अब विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार उसने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह साल के शासन का अंत हुआ है। इस बदलाव से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है, जो विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का असर बाजार में भी तुरंत दिखाई दिया। सेंसेक्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और कोलकाता की कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक स्थिर और स्पष्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। जब राज्य और केंद्र की सरकारें एक दिशा में काम करती हैं, तो निवेश का माहौल बेहतर बनता है। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की यह तेजी शुरुआती प्रतिक्रिया हो सकती है। दीर्घकाल में आर्थिक स्थिति कई अन्य

कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें। उद्योग जगत को उम्मीद है कि अब बड़े आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। निवेश की मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकती है और नियमों में स्पष्टता आएगी। इससे निजी और सरकारी दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार भी राज्य में तेजी से हो सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और मांग बढ़ने की संभावना है। कई उद्योग संगठनों ने भी इस परिणाम का स्वागत करते हुए निवेश के माहौल में सुधार की उम्मीद जताई है। अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, तो आधारभूत ढांचा और निर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सड़क, बंदरगाह और औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिल सकती है। अचल संपत्ति क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद है। चाय, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में नई योजनाएं विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कर्ज वितरण बढ़ सकता है, खासकर छोटे उद्योगों और आवास क्षेत्र में। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है। वित्तीय घाटा और कर्ज का स्तर ऊंचा बना हुआ है। ऐसे में नई सरकार के लिए अपने वादों को संतुलित तरीके से लागू करना जरूरी होगा, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राजनीतिक बदलाव पर्याप्त नहीं है। नीतियों का सही क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन ही लंबे समय में वास्तविक परिणाम तय करेंगे। वैसे आम लोगों के लिए इस बदलाव का अर्थ है संभावित रूप से अधिक रोजगार के अवसर और बेहतर आर्थिक गतिविधियां। अगर निवेश बढ़ता है और उद्योग विकसित होते हैं, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इससे जीवन स्तर और बाजार की स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल अभी भी निवेश के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है। विदेशी निवेश कम रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की गति भी धीमी रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का योगदान अधिक है, जबकि औद्योगिक विकास को और मजबूत करने की जरूरत है। व्यापार करने की सुविधा से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। जमीन की उपलब्धता, मंजूरी की प्रक्रिया और नियमों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सुधार जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक इतिहास कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। एक समय ऐसा था जब यह राज्य अपने कारखानों और उद्योगों के कारण पूरे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान रखता था। दूसरे राज्यों से लोग यहां रोजगार की तलाश में आते थे। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलती चली गई। पहले वामपंथी सरकारों की नीतियों के कारण उद्योगों पर दबाव बढ़ा और धीरे धीरे कई कारखाने बंद होने लगे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और नीतिगत अनिश्चितता को लेकर भी सवाल उठते रहे।

विकास में भेदभाव का शिकार हो रहे हैं प्रमुख तीर्थस्थल

योगेंद्र योगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ससंदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में जहां तरक्की और घोषणाओं की बरसात हो रही है, वहीं देश के दूसरे प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल विकास की बाट जोह रहे रहे हैं। मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा जोर काशी तक सीमित कर रहा गया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि काशी हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए इसके विकास की दरकार है, तो ऐसे में देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य तीर्थ स्थल विकास की दौड़ में काशी से काफी पीछे क्यों हैं। कारण साफ नजर आता है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में विकास की गंगा बह रही, वहीं अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल वाले जिले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपय की लागत से 580 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। काशी के विकास की घोषणाओं की शुरुआत मोदी के पहली बार सांसद बनने के साथ ही शुरु हो गई थी। यह सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 6332 करोड़ रुपये की कुल 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें गंगा पर सिग्नेचर ब्रिज सबसे बड़ी परियोजना है। जिसकी लागत करीब ?2464.46 करोड़ है। यह ब्रिज काशी की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री के हाथों 1054.69 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5277.39 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। काशी के अलावा देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल वाले जिलों में विकास चींटी की रफ्तार से रेंग रहा है या फिर उसकी सुध नहीं ली जा रही है। काशी के अलावा देश के प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों में आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। वैष्णों देवी के लिए प्रसिद्ध कटरा जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान भूस्खलन की गंभीर समस्या है। जम्मू और कटरा के बीच सड़क और रेल संपर्क अक्सर टूट जाता है। विशेष रूप से, 2025 की बाढ़ के बाद से ट्रेनों का रद्दीकरण और पुलों (जैसे कठुआ, उधमपुर के पास) को नुकसान ने यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया है। कटरा में स्मार्ट सड़कों, सुव्यवस्थित पार्किंग, और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मौजूदा सुविधाएं नाकाफी हैं। बढ़ती भीड़ के कारण गर्मियों में पेयजल और निरंतर बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। लगातार निर्माण, वनों की कटाई और भीड़भाड़ के कारण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राम मंदिर के विख्यात अयोध्या में बाल विकास विभाग की एक रिपोर्ट ने जिले में कुपोषण की चिंताजनक स्थिति को उजागर की है। जिले के 2,381 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 2,28,018 बच्चों की जांच में 7,520 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इनमें 1,199 बच्चे अति कुपोषित (सैम) और 6,321 बच्चे मध्यम गंभीर कुपोषित (मैम) श्रेणी में हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 264 और 2024-25 में 286 अति कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया। विकास परियोजनाओं के कारण हजारों लोग, विशेषकर छोटे व्यापारी और गरीब, अपने पुश्तैनी आवासों और व्यवसायों से विस्थापित हो गए हैं। परियोजनाओं के कारण उड़ने वाली धूल और निर्माण सामग्री से स्थानीय लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। जल भराव और सीवर के गंदे पानी के घरों में घुसने की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। पुरानी अयोध्या (फैजाबाद) और अयोध्या धाम के बीच आवागमन में मुश्किल हो रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले के कई सुदूरवर्ती गांव अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बाधित होने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य उपचार के लिए भटकना पड़ता है। भारी बारिश के कारण संपर्क मार्ग बाधित होना भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में एक बड़ी बाधा है। जिले भर में लगभग 25 जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पानी की कमी से नाराज लोग जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, धार्मिक पर्यटन के दबाव और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं। नालों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है।

जनगणना 2027: घर-घर पहुंच रही जनगणना टीम, नागरिक दें सही जानकारी

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

मुख्य जनगणना अधिकारी श्रीमती प्रियंका रजावत के मार्गदर्शन में जनगणना 2027 हेतु खंडवा शहर के 6 जोनों में कुल 307 ब्लॉकों के लिए 307 प्रगणकों एवं 51 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनके अतिरिक्त लगभग 10 प्रतिशत कार्मिक रिजर्व श्रेणी में रखे गए हैं।

समस्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 9 बैचों में पूर्ण कराया जा चुका है। चार्ज अधिकारियों के नेतृत्व में जनगणना दल क्षेत्रवार घर-घर पहुंचकर सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। जनगणना कार्य के दौरान नागरिकों से भवन, मकान, परिवार, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन, डिजिटल सुविधाएं, वाहन, सामाजिक वर्ग सहित निर्धारित 34 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। यह जानकारी शासन द्वारा विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, संसाधन

प्रबंधन एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु महत्वपूर्ण होगी। नागरिकों से अपील की गई है कि जनगणना दल द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का सही, स्पष्ट एवं पूर्ण उत्तर प्रदान करें। सटीक जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है, जिससे जनगणना के आंकड़े प्रमाणिक बनें और भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी रूप से लागू की जा सकें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जो शहर एवं नागरिकों के समग्र विकास की आधारशिला है। अतः सभी नागरिक सक्रिय सहयोग देकर इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं।

ओंकारेश्वर में अतिक्रमण कार्रवाई पर बवाल, पुनर्वास की मांग तेज

जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह मिलें पीड़ितों से, उचित मुआवजे और पुनर्वास की करी मांग

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर लोक निर्माण के नाम पर हो रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा गरीब परिवारों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि उनके पुनर्वास या वैकल्पिक प्लॉट की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में प्रभावित परिवारों के सामने बरसात से पहले ही सिर छुपाने का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों का कहना है कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के उन्हें बेघर कर दिया गया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं है। कुछ मामलों में महिलाओं पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, जबकि एक युवती ऐसी भी है जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना गुजारा कर रही है और अब उसके पास भी रहने का ठिकाना नहीं बचा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ओंकारेश्वर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए

सरकार से मांग की कि गरीबों के आशियाने न तोड़े जाएं और यदि तोड़ना अनिवार्य हो तो पहले उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही स्पष्ट नीति बनाकर पीड़ितों को राहत नहीं दी, तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस परिवार के साथ खड़ी है, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह के साथ चंपा बाई नगर परिषद अध्यक्ष ओंकारेश्वर, रोमी चौकसे, चंद्रकांत महालिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नादान सिंह सोलंकी, सोनू बोरकर,कड़वा कहार, गब्बर, मोड़ा जी सहित बड़ी संख्या में पीड़ित जनमानस एवं कांग्रेसजन मौजूद रहें।

नगर निकाय प्रकोष्ठ खंडवा के जिलाध्यक्ष बने मनोज मंडलोई

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष निशंक जैन द्वारा खंडवा जिले में मनोज मंडलोई को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद कांग्रेस संगठन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मनोज मंडलोई लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव और सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहर) प्रतिभा रघुवंशी,नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर, जिला प्रेमांशु जैन सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने मनोज मंडलोई को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आशा जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी।

खंडवा में कांग्रेस का जश्नः केरल में जीत पर बांटी मिठाइयां, दी शुभकामनाएं

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल में पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा पार्टी की जीत को जनहित की नीतियों की जीत बताया। जश्न के समय उपस्थित जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष(शहर) प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया और भविष्य में भी इसी तरह जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रचना तिवारी,सरोज बघेल,विशाल जैन, मनोज मंडलोई,प्रेमांशु जैन,यशवंत सिलावट,अय्यूब लाला, संजय पाटीदार,धर्मेन्द्र सिंह राठौर,विकास व्यास,इमरान गौरी,अयान,नासिर खान,मुजाहिद कुरेशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने मिलकर पार्टी की सफलता का उत्सव मनाया।

बंगाल में मिली प्रचंड जीत पर वकीलों ने झालमुड़ी विथ प्याज स्पेशल पार्टी का लिया आनंद

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

बंगाल सहित असम और पांडुचेरी में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय और तमिलनाडु और केरलम में सनातन विरोधी सरकार के अवसान से हर्षित भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने चुनाव परिणाम के साथ संघ के बैठक कक्ष में जमकर जश्न मनाया। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि 4 मई सोमवार को पूरे देशवासियों की नजर बंगाल चुनाव के परिणामों पर थी पहली बार

बंगाल की धरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला है, अब देश में गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का कमल खिल चुका है। विधि प्रकोष्ठ द्वारा जीत का जश्न मनाते हुए झालमुडी विथ प्याज स्पेशल पार्टी का आनंद लिया गया, इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ खंडवा के अध्यक्ष रविंद्र पाथरीकर, देवेंद्र सिंह यादव, मोहन गंगराड़े, प्रणय गुप्ता, महेंद्र यादव, विजय चौधरी, पुष्पा गौर, किरण तंवर, प्रशांत मालवीय, मनोज तंवर, विनम्र गंगराड़े, द्वारकादास आसवानी, संतोष गौर, नवीन हनवे,गोपाल जायसवाल, जसवंत परमार, शिवकुमार बारिया, राजेश तिवारी,साकेत धातक सहित बड़ी संख्या में वकील उपस्थित थे।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059